मध्य तथा निम्न आय वर्गों के लोग किराये पर रहते हैं और उनका आमदनी का एक बड़ा भाग किराए के रूप में चला जाता है ,

(ख) क्या सरकार दिल्ली में किराया नियंत्रण के लिए कोई आदर्श विधान बनाने पर विचार कर रही है, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) आवास पर 1991 की जनगणना के आंकड़े की तारीख में उपलब्ध नहीं है । तथापि 1981 की जनगणना के अनुसार, दिल्ली में किराया आवास में रहने वाले परिवारों का प्रतिशत 49 प्रतिशत था । राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण संगठन के 44वें दौरे सर्वेक्षण के अनुसार, दिल्ली में सेम्पल परिवारों द्वारा दिया गया औसत मासिक किराया रुपये 336.80 था ।

(ख) और (ग) प्रस्तावित आदर्श किराया नियंत्रण विधेयक के आधार पर दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन विवेचनाधीन है ।

*169 [Transferred to the 13th May, 1992]

रूस में भारतीय छात्रों को अतिरिक्त राज-सहायता का दिया जाना

@*169-क. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सोवियत रूस में इस समय पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को अतिरिक्त राज-सहायता दिये जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पूववर्ती सोवियत संघ में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था आरम्भ किए जाने के परिणाम स्वरूप निर्वाह लागत के बढ़ जाने के कारण भारतीय छात्रों को परेशानी उठानी पड़ रही है, इस अभ्यावेदन में की गई मांग कब तक स्वीकार कर ली जाएगी, और

(ग) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास कर रही है कि सोवियत रूस में भारतीय छात्रों के अध्ययन में बाधा न आये ।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मास्को स्थित भारतीय दूतावास की सिफारिश पर भूतपूर्व सोवियत संघ में अध्ययन कर रहे उन भारतीय छात्रों को जिन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत भेजा जा चुका था, दुर्लभ मुद्रा में 500 रुपये प्रति मास का भत्ता संस्वीकृत किया । यह 1992 की प्रथम तिमाही के लिए एक अस्थायी उपाय था मास्को स्थित भारतीय दूतावास के इस भत्ते को जारी रखने और उसे बढ़ाने की सिफारिश की है जिस पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) विदेश मंत्रालय स्वतन्त्र राज्यों के राजमंडल और इसके सदस्य गणराज्यों पर इस बात की आवश्यकता पर जोर डालने का प्रयास कर रहा है कि भारतीय छात्रों के संबंध में भूतपूर्व सोवियत संघ द्वारा कि कई सभी वचनबद्धताओं का सम्मान किया जाए । सरकार ने उन छात्रों के माता-पिता को कुछ विनियम सुविधाओं को भी अनुमति प्रदान की है जो स्वयं अपनी और से अथवा कुछ प्राईवेट एजेंसियों के माध्यम से गए हैं ।

Publication of Dr. Ambedkar's works

*170. SHRI GURUDAS DAS GUPTA : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether any proposal has been considered by Government to publish

@पूर्वतः तारांकित प्रश्न 190, 11 मई, 1992 से स्थानान्तरित ।

@Previously Starred Question 7 , transferred from the 30th April, 1992.

Dr. Ambedkar's works in various languages during Dr. Ambedkar's Birth Centenary year; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) Yes, Sir.

(b) The Government has decided to translate and publish 12 volumes of Writings and Speeches of Dr. Ambedkar in Hindi and 8 other languages, viz.. Bengali, Tamil, Telgu, Malayalam, Kannada, Oriya, Punjabi and Gujarati. An amount of Rs. 38 lakhs has been released during 1991-92 to the Publications Division of Ministry of Information & Broadcasting to undertake been provided for this scheme in the annual the work. A provision of Rs. 80 lakhs has Plan 1992-93.

Modernisation of rolling mill in Rourkela Steel Plant

*171. SHRI RAM AWADHESH SINGH: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) what are the names of the companies/firms which have been awarded the work relating to modernisation of Rolling Mill in Rourkela Steel Plant;

(b) whether it is also a fact that some of the firms have been trying to secure the work under the pretext of providing soft loans from Germany; if so, the details thereof;

(c) what are the details of the expenditure involved in the modernisation programme including the foreign exchange component; and

(d) whether Government have dropped the idea of forming a consortium of public sector undertakings in order to provide infrastructure to public as well as private sector enterprises; if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) for the modernisation of the Rolling Mill of Rourkela Steel Plant SAIL/RSP have finanlised/decided placement of orders as follows:—

(i) It has been decided to place order for the Global Package of Hot Strip Mill and Plate Mill modification on the Consortium led by M/s. MANNESMAN DEMAG SACK (MDS), Germany which includes MECON and M/s. Birla Technical Services as Indian associates.

(ii) The order for the indigenous package of Relocation of Dividing Lines has been finalised on MECON.

(iii) Order for the indigenous package of Reheating Furnances for Hot Strip Mill and Plate Mill is yet to be finalised.

(b) The financing proposal for funding the foreign exchange component of the global packages of RSP modernisation was stipulated in the tender specifications of SAIL. The order for the package of the Hot Strip Mill and Plate Mill (modification) intended to be finalised on the Consortium led by M/s. MDS is linked with the financing proposals offered by them from Kreditanstalt Fur Wiederaufban (KFW) (Credit Bureau for Industrial Reconstruction), Germany.

(c) The approved Revised Cost Estimates of the total medernisation scheme of RSP are Rs. 3954 crores inclusive of foreign exchange component of Rs. 714 crores (base date 1st Quarter, 1992 prices).

(d) Government do not have any proposal to form a Consortium of Public Sector Undertakings to provide infrastructural facilities.

Contract Labour System in FCI

*172. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL:

SHRI GHUFRAN AZAM:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether the workers of Food Corporation of India have threatened to paralyse the public distribution system in large parts